भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2408

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2023

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) का कार्यान्वयन

2408. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अभिज्ञात क्षेत्रों में सामुदायिक ढांचा और मूलभूत सुविधाएं निर्मित करना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (UT) प्रशासनों के तत्वावधान में फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है और परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती हैं। इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, नई परियोजनाओं की मंजूरी और धन जारी करना राज्यों में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, व्यय की गति, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि, पीएमजेवीके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 3393.44 करोड़ रुपये की कुल 8107 बुनियादी ढाँचा इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं।

इनमें शिक्षा क्षेत्र में 946.44 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 7432 इकाइयां; स्वास्थ्य क्षेत्र में 1955.59 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 444 इकाइयां; और कौशल विकास क्षेत्र में 84.61 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 20 इकाइयां शामिल है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

*****